उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 20 ₹ 20/- 16-31 मार्च, 2019

कथित भगवा आतंकवाद पर
कांग्रेस बेनकाब

आरएसएस की साजिश 26/11 का विमोचन

स्वामी असीमानन्द

और पढ़ें...

- फिल्म राम जन्मभूमि के बहिष्कार का फतवा
- आतंकवादी मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान-चीन का गठजोड़
- सउदी युवराज का अपने विरोधियों के खिलाफ अभियान
- पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 20

16-31 मार्च, 2019

परामर्शदाता

प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक

मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग

शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार

सुधीर कुमार सिंह

(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय

डी-51, प्रथम तल,

हौज खास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018

ईमेल : indiapolicy@gmail.com

वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा

भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए

डी-51, प्रथम तल, हौज खास,

नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित

तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,

ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,

नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. कथित भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस बेनकाब

II. आतंकवादियों को खाड़ी देशों से सहायता

III. जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट पर प्रतिबंध

IV. आरएसएस के पास चुनाव की चाभी?

V. फिल्म राम जन्भूमि के बहिष्कार का फतवा

VI. बिहार में मुसलमानों के साथ अन्याय?

विश्व

I. न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमला

II. आतंकवादी मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान-चीन का गठजोड़

III. पाकिस्तान में पत्रकार निशाने पर

IV. काबूल में छह आतंकवादी गिरफ्तार

V. ब्रिटेन में मस्जिदों पर हमले

VI. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज अशरफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

VII. ईसाई महिला को जबरन मुसलमान बनाने के आरोप की जांच

पश्चिमी एशिया

I. ईरान और इराक के बीच संबंध सुधारने का प्रयास

II. यमन में हाउसी विद्रोहियों द्वारा भर्ती

III. सउदी युवराज के विरोधियों के खिलाफ अभियान

IV. कतर द्वारा तुर्की से टैंकों की खरीद

V. ईरानी आतंकवादियों को सजा

VI. ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी

VII. इस्लामिक स्टेट का खात्मा?

अन्य

I. इलाहाबाद का नाम बदलने पर खटखटाया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा

II. जम्मू-कश्मीर में नए राजनीतिक दल की घोषणा

III. पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण

IV. वक्फ संपत्ति के अवैध कब्जे को मुक्त करवाने के लिए अभियान

V. कराची में इस्लामी नेता पर हमला

VI. चीन में 13 हजार जिहादी गिरफ्तार

सारांश

कांग्रेस सरकार ने हिन्दू संगठनों को बदनाम करने के लिए तथाकथित भगवा आतंकवाद का जो ताश के पत्तों का महल तैयार किया था वह अब तेजी से बिखरने लगा है। समझौता एक्सप्रेस में 12 वर्ष पूर्व हुए धमाकों के केस में एनआईए की विशेष न्यायालय ने स्वामी असीमानंद सहित तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पूर्व मक्का मस्जिद धमाका केस, मालेगांव धमाका केस और अजमेर दरगाह धमाका केस के कथित आरोपी साफ बरी हो चुके हैं। भगवा संगठनों को जनता की नजर में बदनाम करने के लिए पिछली कांग्रेसी सरकार ने जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर एक अभियान चलाया था। समझौता एक्सप्रेस धमाका केस के जांच अधिकारी गुरदीप सिंह ने यह स्वीकार किया कि इस धमाके के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था और उसने अपने जुर्म को भी कबूल कर लिया था। मगर उच्च अधिकारियों के दबाव पर इस पाकिस्तानी अजमत अली के खिलाफ न्यायालय में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए जिसके कारण न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया था। भगवा आतंकवाद का शोशा सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छोड़ा था और उनके स्वर में स्वर मिलाने के लिए तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और कई अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हो गए थे। मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकवादी हमले को भी संघ परिवार से जोड़ने का प्रयास किया गया। एक विवादित पत्रकार अजीज बर्नी से इस संबंध में एक पुस्तक 'आरएसएस की साजिश 26/11' भी लिखवाई गई जिसका विमोचन कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। अगर पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब घटनास्थल पर नहीं पकड़ा जाता तो इस मामले में भी संघ के कई नेताओं को फंसाने की तैयारी हो चुकी थी।

कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ के चंगुल से बचाने के लिए चीन बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान का साथ देने के लिए मैदान में कूद पड़ा है और चौथी बार उसने अपने वीटो का प्रयोग करके इस कुख्यात आतंकवादी को बचा लिया है।

पश्चिमी देशों में इस्लाम के बारे में जो वातावरण पैदा हो रहा है उसकी खौफनाक परिणति न्यूजीलैंड में हुई। एक जुनूनी व्यक्ति ने वहां के दो मस्जिदों पर हमला करके अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब मुस्लिम समाचारपत्र इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि न्यूजीलैंड में इस्लाम का बोलबाला हो गया है।

मुस्लिम उलेमा मनमाने ढंग से विवादास्पद फतवे जारी करने में जुटे हुए हैं। हाल में ही मध्यप्रदेश के दो मुस्लिम उलेमाओं ने फतवे जारी करके मुसलमानों से यह अपील की है कि वे फिल्म राम जन्मभूमि का बहिष्कार करें। इन्होंने सरकार पर इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया है।

इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने का मामला अभी सुलझ नहीं पा रहा है। कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय

I

कथित भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस बेनकाब

सियासत (21 मार्च) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के बाद हरियाणा की एक न्यायालय ने इसके प्रमुख अभियुक्त स्वामी असीमानंद और अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। इस धमाके में 68 लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकांश पाकिस्तानी थे। हालांकि इस धमाके में दस हिन्दुस्तानी नागरिक भी मारे गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वकील राजन मलहोत्रा ने कहा कि न्यायालय ने चारों आरोपी नब कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेन्द्र चौधरी को बरी कर दिया है। वकील ने कहा है कि जहां तक इस फैसले के खिलाफ अपील करने का सवाल है इस मुद्दे पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायाधीश जगदीश सिंह ने इस फैसले को सुनाया। इससे पूर्व उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला की याचिका को रद्द कर दिया जिसमें इस महिला ने न्यायालय से आग्रह किया था कि उसे इस मामले में गवाही देने का अवसर दिया जाए। ज्ञातव्य है कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच एक विशेष रेलगाड़ी के तौर पर सप्ताह में दो दिन चलती है। जब यह गाड़ी दिल्ली से अटारी जा रही थी तभी रास्ते में पानीपत के समीप इसमें कई धमाके हुए थे। समाचारपत्र के अनुसार इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग को अपने दफ्तर में तलब करके समझौता एक्सप्रेस के चारों आरोपियों के रिहाई के खिलाफ विरोध प्रकट किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसे मजाक बताया है और कहा है कि न्यायालय यह बताए कि धमाका करने वाले कौन थे?

अखबार-ए-मशरिक (23 मार्च) के अनुसार जमीयत-ए-उलेमा के सचिव गुलजार आजमी ने यह आरोप लगाया है कि अरोपियों की रिहाई एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जानबूझकर न्यायालय के सामने ठोस सबूत पेश नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण राष्ट्रीय जांच एजेंसी जानबूझकर एक विशेष विचारधारा के आरोपियों को बरी करवा रही है। यही कारण है कि मालेगांव बम धमाका केस, मक्का मस्जिद बम धमाका केस और जालना मस्जिद बम धमाका केस के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। आजमी ने कहा कि स्वामी असीमानंद ने दिल्ली में बयान देकर यह स्वीकार किया था कि इन सभी धमाकों में उनका हाथ था जिनमें दर्जनों मुसलमान मारे गए थे। जांच के बाद भगवा आरोपी पकड़े गए लेकिन उन्हें रिहा कराने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया।

अखबार-ए-मशरिक ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि अगर समझौता एक्सप्रेस धमाके के लिए कोई दोषी नहीं है तो यह धमाका करने वाले क्या भूत-प्रेत थे? समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकार बदलते ही गवाहियां भी बदल जाती हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले की निंदा की है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से यह मांग की है कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करती तो यह समझा जाएगा कि वह जानबूझकर साम्प्रदायिकता को हवा दे रही है।

II

आतंकवादियों को खाड़ी देशों से सहायता

सियासत (18 मार्च) के अनुसार कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर ने सन् 1994 में भारत आने से पहले इंग्लैण्ड, खाड़ी देशों और अफ्रीका का दौरा किया था ताकि कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की जाए। इस दौरे

में उसे 15 लाख रुपये भी प्राप्त हुए। 1992 में उसने ब्रिटेन का दौरा किया और उसके साथ साउथ हॉल मस्जिद के इमाम मुफ्ती इस्माइल भी था। इन दोनों ने ब्रिटेन में अनेक नगरों का दौरा करके वहां से भारी मात्रा में चंदा इक्ट्ठा किया। जब उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से यह धनराशि बरामद हुई थी। इससे पूर्व उसने लखनऊ, सहारनपुर और दारूल उलूम देवबंद का भी दौरा किया था और वह ढाका भी गया था। बाद में उसने श्रीनगर का दौरा किया। उसके साथ कुछ अफगान आतंकवादी भी थे। अनंतनाग में उसने सज्जाद अफगानी से हरकत–उल–जिहाद–अल–इस्लामी के दफ्तर में मुलाकात की।

सियासत ने एक अन्य समाचार में कहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर हाफिज सईद ने वैश्विक आतंकी सूची से अपना नाम हटवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में जो अर्जी दी थी उसे उसने अस्वीकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के राजदूत मलीहा लोधी ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज किया गया है उसके पीछे भारतीय मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय मीडिया ने उसे 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का दोषी करार दिया था और मीडिया ने उसकी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जो विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसके कारण पाकिस्तान का प्रयास विफल रहा।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (13 मार्च) के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात–उद–दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन से धन लेकर उसे जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचाने के एक आरोपी कारोबारी जहूर वटाली की गुड़गांव स्थित संपत्ति को जब्त कर लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वटाली पाकिस्तान से मिलनेवाली धनराशि को आतंकवादियों को उपलब्ध कराता रहा है। हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं को दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास से भी भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त होती रही है। इस संबंध में हाल में ही गुलाम बट नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से काफी आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था। यह व्यक्ति जहूर वटाली के पास कैशियर के रूप में कार्य करता था। जांच में पाया गया कि वटाली ने पाकिस्तानी दूतावास से भारी राशि प्राप्त की और उसे आतंकवादियों तक पहुंचाया। इसके अतिरिक्त उसने दुबई से भी काफी धनराशि प्राप्त की थी जिसे उसने हुर्रियत नेता, आतंकवादियों और पत्थरबाजों तक पहुंचाया था। वटाली और उसका एक बेटा गुड़गांव के एक अस्पताल में डॉक्टर हैं। पुलिस के अनुसार जो संपत्ति जब्त की गई है उसकी कीमत एक करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है।

III

जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट पर प्रतिबंध

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (23 मार्च) के अनुसार पृथक्कतावादी नेता यासीन मलिक के संगठन जम्मू–कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस संगठन द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे पूर्व जमात–ए–इस्लामी जम्मू–कश्मीर पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। हुर्रियत कांफ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को रिजवान पंडित की मौत के खिलाफ प्रदर्शन करने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। ज्ञातव्य है कि गत दिनों अवंतीपुरा में रिजवान पंडित की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। एक अन्य समाचार के अनुसार सरकार ने श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे के नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा सैनिकों ने जामा मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए ताकि लोग उसमें दाखिल होकर नमाज न पढ़ सकें। मीरवाइज उमर फारूक ने नमाज पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है और कहा है कि हम इस्लाम पर इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार हमारे धार्मिक मामले में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप कर रही है।

IV

आरएसएस के पास चुनाव की चाभी?

साप्ताहिक नई दुनिया (25 मार्च) के अनुसार मोदी सरकार को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैदान में कूद पड़ा है। भाजपा के चुनाव अभियान की बागडोर स्वयंसेवक सम्भालेंगे और वे जनता में काम करके मोदी सरकार के प्रति नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह निर्णय ग्वालियर में हुई आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में किया गया। स्वयंसेवकों को कहा गया है कि वे मतदान केन्द्रों पर ज्यादा ध्यान दें। इस उद्देश्य से सभी मतदान केन्द्रों के लिए ग्रुप बनाए गए हैं जो मतदाताओं में भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने की जिम्मेवारी भी निभाएंगे। संघ ने यह भी फैसला किया है कि संघ से संबंधित सभी संगठनों में तालमेल को बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवकों को मतदाताओं को यह समझाने की भी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि राम मंदिर हर हाल में निर्धारित जगह पर निर्धारित मॉडल में ही बनेगा। हालांकि इसमें कुछ देरी लग सकती है, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस बैठक में मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी।

एक अन्य समाचार में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान का भय दिखाकर अमित शाह वोटों की फसल को काटना चाहते हैं। अमित शाह का कहना है कि मोदी के बिना देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर मोदी नहीं होंगे तो पाकिस्तान हिन्दुस्तान को खा जाएगा। समाचारपत्र ने कहा है कि किसानों और युवकों का मोदी सरकार से मोह भंग हो रहा है। राफेल डील मोदी सरकार की गले की फांस बन गया है। मीडिया का जादू प्रभावहीन हो रहा है। मंदिर और पकौड़ों का फार्मूला विफल हो गया है। लोग पूछने लगे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे? हवा के रूख को देखते हुए अब भाजपा ने लोकसभा में 250 सीटों को ही जीतने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है।

V

फिल्म राम जन्भूमि के बहिष्कार का फतवा

सियासत (20 मार्च) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर भोपाल का एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के दो मुस्लिम इमामों ने यह फतवा दिया है कि मुसलमान राम जन्मभूमि फिल्म को न देखें। इसके साथ इस फिल्म में काम करने वाली मुस्लिम महिला को इस फिल्म से तौबा करने और इस्लाम पर पुनः आस्था व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने केन्द्र और मध्य प्रदेश की सरकारों से मांग की है कि इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाने का कार्य कर रही है। उलेमा बोर्ड ने यह भी दावा किया है कि यह फिल्म उस समय रिलीज की जा रही है जब सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ बनकर इस विवाद को हल करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर इस फिल्म को रिलीज करके समाज में नया वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी इस फिल्म के लेखक और प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म में राम जन्मभूमि विवाद की कहानी को पेश किया गया है। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल मध्यप्रदेश यूनिट के उपाध्यक्ष नूर उल्लाह युसूफ जई ने कहा है कि इस फिल्म के रिलीज पर लोकसभा के चुनाव पूर्ण होने तक रोक लगा दी जाए, ताकि समाज के दोनों वर्गों में नफरत फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण न किया सके।

फतवे में आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म में राम जन्मभूमि मुद्दे को गलत रूप में पेश किया गया है और इसमें इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है। उन्होंने कहा कि उलेमा बोर्ड शरियत और इस्लाम का मजाक सहन नहीं करेगा। इस फिल्म में निकाह, हलाला और तलाक को भी गलत ढंग से पेश किया गया है।

VI

बिहार में मुसलमानों के साथ अन्याय?

हमारा समाज (24 मार्च) के अनुसार बिहार में एनडीए ने लोकसभा के उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें मुस्लिम उम्मीदवार गायब हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने सिर्फ एक सीट पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी अपने पूर्व मुस्लिम केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का पत्ता काट दिया है। एनडीए ने बिहार की 40 सीटों में से 39 पर जो सूची जारी की है उसमें सिर्फ किशनगंज सीट से महमूद अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। 2009 में भी इसी सीट से जेडीयू ने अशरफ को खड़ा किया था। 2014 के चुनाव में जेडीयू ने बिहार में पांच मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें शिवहर से शाहिद अली खान, मधुबनी से गुलाम गौस, किशनगंज से अख्तरूल इमान, शारण से सलीम परवेज और भागलपुर से अबू कैसर शामिल हैं। इससे पूर्व 2004 में जेडीयू ने डॉ. मंजर हुसैन को मुंगेर से और 2009 में उन्हें बेगुसराय से अपना उम्मीदवार बनाया था। जहां तक शाहनवाज हुसैन का संबंध है पिछली बार शाहनवाज ने भागलपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आठ हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। इससे पूर्व 2004 में इस सीट से जीतने वाले बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और वहां पर 2006 में हुए उपचुनाव में शाहनवाज हुसैन जीत गए थे। उसके बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भी शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर से अपनी जीत दर्ज की थी। शाहनवाज पहली बार 1999 में किशनगंज क्षेत्र से जीते थे। 2004 में उन्हें इसी क्षेत्र से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था मगर वे आरजेडी उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन से हार गए। 2019 में एनडीए में हुए सीटों के तालमेल के कारण भागलपुर की सीट जेडीयू के खाते में चली गई और उसने वहां पर अजय कुमार मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकजनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है मगर उसने किसी भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 2014 में इस पार्टी ने महबूब कैसर को चुनावी दंगल में उतारा था और वे यह चुनाव जीत गए थे।

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार आने वाले चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से अनेक मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और वे एक दूसरे का वोट काटने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अमरोहा की सीट से राशिद अल्वी चुनाव लड़ रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और राष्ट्रीय लोकदल ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार कुंवर दानिश अली को खड़ा किया है। ज्ञातव्य है कि दानिश अली गत दिनों जेडीएस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। इसी तरह से कांग्रेस ने मुरादाबाद क्षेत्र से इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है और उनके मुकाबले में सपा बसपा ने अपना संयुक्त उम्मीदवार एचटी हुसैन को खड़ा किया है। कांग्रेस ने बिहार के तीन मुसलमान उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इनमें कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद शामिल हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान को मैदान में उतारा है।

विश्व

I

न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमला

इंकलाब (16 मार्च) के अनुसार न्यूजीलैंड के तीसरे सबसे बड़े नगर क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हुए हमले में 49 लोग मारे गए और 39 जख्मी हो गए। पुलिस ने इस संबंध में एक महिला सहित चार आक्रमणकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आस्ट्रेलिया का रहने वाला है। अभी यह पता नहीं चल सका है कि इन आक्रमणकारियों की पृष्ठभूमि क्या है? और इन लोगों ने इस तरह का हमला क्यों किया? ज्ञातव्य है कि 42 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में मुसलमानों की आबादी लगभग 46 हजार है। समाचारों के अनुसार आक्रमणकारियों ने मस्जिदों पर हमले से पूर्व कैमरे से वीडियो बनाई थी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने इस हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताया है और चार लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। एक अन्य समाचार के अनुसार मरनेवालों में नौ भारतीय भी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मारनेवालों का सम्बन्ध अतिवादियों से है।

अन्य समाचारों के अनुसार इस हमले के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों में जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई है और इसे नस्लपरस्ती और फासीवाद बताया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे विश्व में फैल रहे इस्लाम विरोधी भावना का कारण बताया है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए न्यूजीलैंड सरकार से मांग की है कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इंडोनेशिया सरकार ने कहा है कि मरनेवालों में तीन इंडोनेशिया के नागरिक भी शामिल हैं। मलेशिया की सरकार ने इसे मानवता पर हमला करार दिया है। तुर्की ने इस हमले को नस्लपरस्ती का कारण बताया है और कहा है कि इस्लाम जिस तेजी से विश्व में फैल रहा है उसके कारण लोग उससे भयभीत हो रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि घायल होने वालों में तीन अफगान नागरिक भी हैं। जर्मनी और रूस ने भी इस हमले की निंदा की है।

जामा मस्जिद, दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी ने इस घटना की निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जमीयत-ए-उलेमा के नेता अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए यह बहुत नाजुक समय है इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईरान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से हुई भेंट में इस हमले की निंदा की है और कहा है कि ईरान और भारत को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए।

समाचारपत्र ने इस संबंध में अपने संपादकीय में कहा है कि अब तो बाजारों, उपासना स्थलों और स्कूलों में निहत्थे और बेगुनाहों को मारना एक फैशन बन गया है। न्यूजीलैंड में चंद सिरफिरे ईसाईयों ने 50 से ज्यादा मुसलमानों की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उनकी नजर में उन्हें जीने का हक नहीं था। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि हत्यारों को कोई ईसाई आतंकवादी नहीं बता रहा है। अगर किसी चर्च में प्रार्थना करनेवालों पर इसी तरह से हमला किया जाता तो सारी दुनिया इसे इस्लामी आतंकवाद का नाम देकर आसमान को सिर पर उठा लेती।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने 16 मार्च के अंक में शमीउल्लाह खान का एक विशेष लेख प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि ईसाई हमेशा से मुसलमानों के खून के प्यासे रहे हैं और यह हमला मुसलमानों के खिलाफ ईसाईयों की नफरत का सबूत है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के पीछे यहूदियों और ईसाईयों दोनों का हाथ है।

हमारा समाज (16 मार्च) ने अपने संपादकीय में नमाजियों पर हुई गोलीबारी को कायरतापूर्ण हरकत बताया है और कहा है कि विश्व में मुसलमानों के खिलाफ जो वातावरण बनाया जा रहा है यह उसी का नतीजा है। समाचारपत्र ने मांग की है कि इस हमले की साजिश का पूरा पता लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

हमारा समाज (18 मार्च) के अनुसार न्यूजीलैंड पुलिस ने कहा है कि दो मस्जिदों में हुई फायरिंग के मामले में जिन चार लोगों को हिरासत में लिया गया था उनमें से तीन का इस घटना से कोई संबंध नहीं है इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अन्य समाचार के अनुसार केन्द्रीय जमीयत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी ने न्यूजीलैंड में नमाजियों पर हुए हमलों की निंदा की है और यह मांग की है कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। दिल्ली में कई जगह पर मरने वालों की हमदर्दी में कैंडल मार्च भी निकाले गए हैं।

हमारा समाज ने अब्दुल अनवर का एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें यह चेतावनी दी गई है कि भारत में भी मस्जिदों पर हमले हो सकते हैं। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि जिस व्यक्ति ने न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमला किया है उसने पिछले वर्ष पाकिस्तान का दौरा किया था।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (18 मार्च) ने न्यूजीलैंड में हुए हमले पर कई विशेष पृष्ठ प्रकाशित किए हैं जिनमें इस हमले के अनेक चित्र प्रकाशित किए गए हैं। एक लेख में आक्रमणकारी को मानसिक रूप से रोगी बताने के प्रयासों की निंदा की गई है और कहा गया है कि यह हमला पूरी योजना के साथ इस्लाम विरोधी ताकतों ने किया था। एक अन्य लेख शकील अख्तर का है जिसमें कहा गया है कि सारे विश्व में इस्लाम के खिलाफ जो घृणा का प्रचार किया जा रहा है यह हमला उसी का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज में नफरत और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जबकि प्रियंका गांधी ने मरने वालों के साथ सहानुभूति प्रकट की है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व में इस्लाम के खिलाफ जो घृणा फैलाई जा रही है उसको रोकने की जरूरत है वरना उसके भीषण परिणाम होंगे।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार ब्रिटेन की पुलिस ने न्यूजीलैंड में हमले का सोशल मीडिया पर समर्थन करने वाले एक 24 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार तहरीक अवाम-ए-हिन्द ने इस हमले को एक सोची समझी साजिश बताया है। दारूल उलूम देवबंद के छात्रों ने नगर में कैंडल मार्च किया और मांग की कि इस हमले के आरोपियों को विश्व स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जाए। एक अन्य समाचार में न्यूजीलैंड पुलिस के प्रमुख ने यह दावा किया है कि दोनों मस्जिदों पर हमला करनेवाला एक ही व्यक्ति था।

इंकलाब (17 मार्च) ने एक समाचार में यह दावा किया है कि इस हमले में तीन भारतीयों की मौत हो गई है। इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बरेली में शांति समिति ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देकर यह मांग की है कि इस हमले में जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें भारत लाया जाए। एक अन्य समाचार के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में कैंडल मार्च और मरनेवालों के लिए दुआ भी की गई।

इंकलाब ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह घटना कोरा आतंकवाद है। इसे जिहाद या धर्मयुद्ध नहीं कहा जा सकता। इस संपादकीय में इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ होने का संदेह भी व्यक्त किया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि आतंकवाद के बारे में पश्चिमी देशों की दोहरी नीति है। एक अन्य समाचार में यह कहा गया है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने काले कपड़े पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर इस हमले में मरनेवालों के परिवारजनों के साथ शोक व्यक्त किया है। एक अन्य

समाचार में कहा गया है कि क्राइस्टचर्च में मस्जिदों पर हमला करने वाले ने अपने बंदूक पर ईसाईयों द्वारा मुसलमानों की हत्या किए जाने की घटनाओं का उल्लेख किया है।

सहाफत (17 मार्च) के अनुसार आस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा है कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुसलमानों के आने के बाद हिंसा के घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम और आतंकवाद के बीच गहरा सम्बन्ध है। सहाफत ने अपने संपादकीय में न्यूजीलैंड जैसे शांतिप्रिय देश में आतंकवाद की इस घटना पर हैरानी प्रकट की है और दावा किया है कि इस हमले के लिए काफी दिनों से योजना बनाई जा रही थी। समाचारपत्र ने इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

हमारा समाज (17 मार्च) के अनुसार जमाते इस्लामी के प्रमुख मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने विश्व में इस्लाम के खिलाफ सुनियोजित ढंग से हो रहे घृणा प्रचार को रोकने की मांग की है, तो दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख अबुल कासिम नुमानी ने मांग की है कि दोषियों को आतंकवाद विरोधी कानून में सख्त सजा दी जाए। इसी समाचारपत्र में इस संदर्भ में एक सम्पादकीय भी लिखा गया है जिसका शीर्षक है, 'भरोसे का खून'। इस संपादकीय में कहा गया है कि न्यूजीलैंड सरकार की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। आखिर उसकी सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के बारे में सरकार को पूर्व सूचना देने में क्यों विफल रही हैं? एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस घटना को एक जालिमाना हरकत बताया है और इस हमले का शिकार होने वालों को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (17 मार्च) ने इस संदर्भ में कई लेख प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष सम्पादकीय में कहा गया है कि विश्व भर में इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करने का जो दुष्प्रचार चल रहा है यह घटना उसी का नतीजा है। समाचारपत्र ने लिखा है कि आक्रमणकारी ने जो घोषणापत्र प्रसारित किया है उससे साफ है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के मुस्लिम विरोधी अभियान से मानसिक रूप से प्रभावित था।

अखबार-ए-मशरिक (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में न्यूजीलैंड की घटना पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि न्यूयॉर्क में 9/11 के घटना के बाद विश्व में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा फैलाई जा रही है यह उसी का नतीजा है। समाचारपत्र ने मुस्लिम संगठनों से यह आग्रह किया है कि वह दुनिया के साथ यह सच्चाई पेश करे कि इस्लाम शांति का धर्म है और उसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है।

दावत ने 19 मार्च के संपादकीय में इस घटना को दुनिया में इस्लाम के खिलाफ चल रही लहर का कारण बताया है और कहा है कि न्यूजीलैंड में इस्लाम और मुसलमानों को किसी से खतरा नहीं था क्योंकि उनकी जनसंख्या केवल 46 हजार की है। लेकिन यह जरूर है कि गत कुछ वर्षों में अफगानिस्तान और इराक से काफी लोग न्यूजीलैंड आए हैं। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि न्यूजीलैंड की सरकार इस सारी साजिश का पर्दाफाश करने में सफल होगी।

न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों पर हुए हमले के बाद वहां पर इस्लाममय वातावरण बनाने का अभियान तेज हो गया है। **इंकलाब** (18 मार्च) के अनुसार न्यूजीलैंड के संसद का अधिवेशन शुरू होने से पहले कुरान का पाठ किया गया। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार इस हमले के बाद वहां पर इस्लाम धर्म का प्रसार तेज हो गया है और इस हमले के बाद साढ़े तीन सौ व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस हमले के बाद न्यूजीलैंड में लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इससे पहले भी न्यूजीलैंड में इस्लाम बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा था।

हमारा समाज (23 मार्च) के अनुसार न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार जुमा की नमाज और अजान को सरकारी रेडियो और टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया। एक अन्य समाचार के अनुसार न्यूजीलैंड में बाइकर गैंग ने मस्जिदों पर पहरा देने का निर्णय किया है ताकि भविष्य में मुसलमानों को पूर्ण सुरक्षा मिल सके। एक अन्य संगठन मोंगेरल मॉब ने घोषणा की है कि वे हैमिल्टन

नगर की मस्जिदों पर हर जुमा की नमाज के समय पहरा देंगे। एक अन्य समाचार के अनुसार न्यूजीलैंड की गैर-मुस्लिम महिलाओं ने जुमा के दिन मुस्लिम महिलाओं की तरह हिजाब पहना और इस हत्याकांड की निंदा की। मस्जिद अल नूर के इमाम जमाल फौदा ने दावा किया है कि न्यूजीलैंड के नागरिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे इस देश में आतंकवाद किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। समाचारपत्र के अनुसार इस हमले में मारे जाने वाले व्यक्तियों की नमाज-ए-जनाजा अदा की गई। इमाम ने कहा कि विभिन्न नेताओं की ओर से इस्लाम के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था यह हमला उसी का नतीजा है। एक अन्य समाचार के अनुसार आक्रमणकारी की बहन ने इस घटना की निंदा की है और मांग की है कि उसके भाई को फांसी दी जाए।

दैनिक सहाफत (23 मार्च) के अनुसार न्यूजीलैंड के अनेक समाचारपत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित करने के बजाय इस्लाम प्रकाशित करके मुसलमानों के साथ एकजुट होने का प्रयास किया है। दुनिया के इतिहास में यह पहला अवसर है जब इस तरह से समाचारपत्रों ने कदम उठाया हो। जुमा की नमाज से पूर्व न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कुरान का पाठ किया और हदीस पढ़कर सुनाई। एक अन्य समाचार के अनुसार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री को ट्विटर पर एक बंदूक की तस्वीर भेजी गई है और कहा गया है कि अब आपकी बारी है।

सियासत (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में न्यूजीलैंड में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि अगर विश्व में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार न रोका गया तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे और सारी दुनिया में मुसलमानों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि विश्व में मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है जिसके कारण अनेक देशों में मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया।

दैनिक अखबार-ए-मशरिक (23 मार्च) का शीर्षक है- 'पूरे न्यूजीलैंड में अल्लाह अकबर की गूंज'। लगभग अन्य उर्दू समाचारपत्रों ने भी इसी बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस्लामी देशों के सहयोगी संगठन की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पश्चिम में इस्लाम व मुस्लिम विरोधी भावनाओं के उभार पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि न्यूजीलैंड में जो हमला हुआ है वह किसी जुनूनी की हरकत नहीं बल्कि पश्चिम में इस्लाम विरोधी जो लहर चल रही है यह उसी का नतीजा है। उन्होनें इस अधिवेशन को बुलाने के लिए तुर्की को धन्यवाद दिया और कहा कि विश्व में जहां-जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है। उन्हें श्वेत जातियों पर बोझ बताया जा रहा है और इसके लिए मीडिया का भी बड़ी बेशर्मी से इस्तेमाल किया जा रहा है।

दावत (25 मार्च) ने न्यूजीलैंड में हुए आतंकवादी हमले पर टिप्पणी करते हुए अपने संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि जिन देशों में इस्लाम विरोधी प्रचार चल रहा था अब वहां जुमा की अजान सरकारी रेडियो और टीवी पर प्रसारित की जा रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि यदि पुलवामा आतंकी हमले में संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में बहस हो सकती है तो न्यूजीलैंड में हुए मुसलमानों पर आतंकी हमले पर बहस न होने का क्या तुक हो सकता है?

इंकलाब (24 मार्च) ने एक विशेष लेख में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि न्यूजीलैंड के वातावरण में अल्लाह अकबर की सदाएं गुंजने लगी हैं। जुमा की नमाज के बाद वहां पर लोग मस्जिदों के बाहर मुसलमान नमाजियों के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। मस्जिदों के बाहर शहीदों की याद में मोमबतियां जलाई जा रही हैं। स्कूलों में बच्चे हम सब शर्मिंदा हैं लिखकर मुसलमान भाईयों को अपने समर्थन का परिचय दे रहे हैं। एक अन्य लेख में कहा गया है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इन हमलों के बाद जो व्यवहार अपनाया है वह विश्व के लिए एक उदाहरण है।

II

आतंकवादी मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान-चीन का गठजोड़

इंकलाब (14 मार्च, 2019) के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में चौथी बार चीन ने फिर रूकावट डाल दी है। चीन द्वारा वीटो का प्रयोग किए जाने के कारण यह प्रस्ताव रद्द हो गया है। ज्ञातव्य है कि 2017 में भी चीन ने ऐसा ही किया था। चीन का कथन है कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। चीन का कहना है कि अभी तक जो जांच की गई है उसमें मसूद के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। भारत ने दो टेप्स इसके बारे में दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित होने ही वाला था कि चीन ने इसमें अडंगा लगा दिया।

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार चीन द्वारा वीटो इस्तेमाल करने के फलस्वरूप देश की राजनीति में हलचल मच गई है। आनेवाले चुनाव में यह मुख्य मुद्दे के रूप में उभरने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाया है और कहा है कि मोदी चीन से डरे हुए हैं। जब चीन भारत के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मोदी की चीन डिप्लोमैसी गुजरात में चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला-झूलने, दिल्ली में गले लगाने और चीन में घुटने टेकने की रही है। इसका जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया है और कहा है कि जब भारत को तकलीफ होती है तो उसपर राहुल गांधी को क्यों खुशी होती है? उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन आतंकवाद के मामले में इस तरह की भूमिका गलत है। उन्होंने कहा कि 2009 में जब यूपीए सरकार ने मसूद अजहर के खिलाफ इसी तरह का कदम उठाया था तो भी चीन का रवैया यही था। उन्होंने कहा कि राहुल के तो चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। वे उसे क्यों नहीं समझाते?

इंकलाब ने 15 मार्च के अपने सम्पादकीय में कहा है कि चीन ने वही किया है जिसकी उससे आशा थी। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के पक्ष में थे लेकिन चीन ने किसी की परवाह न करके उसका विरोध किया। चीन को दुनिया की परवाह नहीं। दक्षिणी चीन के समुद्र के मामले में उसने विश्व न्यायालय के फैसले को भी ठुकरा दिया था। मसूद अजहर के बारे में चीन ने जो रूख अपनाया उसपर न्यूज चैनलों में काफी चर्चा हुई। किसी ने कहा कि चीन पर डिप्लोमैटिक दबाव डाला जाए तो किसी ने चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त करने की मांग की। लंदन में रहने वाले एक बलोच नेता ने तो यहां तक कह डाला कि भारत को बलूचिस्तान में वैसी ही हरकतें करनी चाहिए जैसा की पाकिस्तान कश्मीर में करता है। ऐसे सुझाव पर हंसने के अलावा और क्या किया जा सकता है? रविशंकर प्रसाद ने तो कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं किया था? मगर इस मंत्री ने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि जब वाजपेयी के शासनकाल में भारतीय संसद पर हमला हुआ था तो वाजपेयी जंग नहीं होने दूंगा का राग क्यों अलाप रहे थे? और बीजेपी ने इसी आतंकवादी को क्यों छोड़ा था? भारत ने चीन के सामने कभी मसूद अजहर के मामले को उठाया ही नहीं। कोई कहता है कि मोदी की ताकत के सामने चीन ने घुटने टेक दिए। कोई कह रहा है कि चीन ने मोदी की ताकत को पहचाना है। कोई कह रहा था कि चीन का दिमाग मोदी ने सही कर दिया है। सोशल मीडिया पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का अभियान भी शुरू हो गया है।

सहाफत ने 15 मार्च के सम्पादकीय में कहा है कि भारत की अनथक प्रयासों पर चीन ने फिर पानी फेर दिया है। इससे पूर्व भी वह तीन बार भारत के प्रयासों को विफल कर चुका है। पाकिस्तान के इशारे पर चीन भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है तो उसे आतंकवाद के विरूद्ध डंटकर अभियान छेड़ना चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक ने 16 मार्च के संपादकीय में चीन द्वारा वीटो के इस्तेमाल करने की निंदा की है और कहा है कि इससे दक्षिणी एशिया का अमन और चैन खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान सरकार वहां की सेना और खुफिया संगठन आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें हर तरह से सहायता प्रदान करते हैं। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि कई आतंकवादी संगठन समाज कल्याण की आड़ में आतंकवाद की दुकान चला रहे हैं। समाचारपत्र ने इस बात की निंदा की है कि पाकिस्तान के साथ अंधी दोस्ती के कारण चीन जानबूझकर आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।

मसूद अजहर के बारे में चर्चा करते हुए **दावत** (19 मार्च) ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए संबंध चीन को पसंद नहीं है इसलिए वह मसूद अजहर के मामले को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि जिस तरह से हिन्दुस्तान मसूद अजहर को अपना दुश्मन समझता है इसी तरह से चीन भी दलाई लामा को अपना दुश्मन समझता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कर भी दिया जाता है तो इससे भारत की क्या उपलब्धि होगी? हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है लेकिन वह आज भी पाकिस्तान में खुलेआम जलसे करता है और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है।

साप्ताहिक जदीद मरकज़ (17 मार्च) ने इस घटना को मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता बताया है और कहा है कि सरकार चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने में विफल रही है।

दैनिक इत्तेमाद (15 मार्च) ने अपने संपादकीय में यह भविष्यवाणी की है कि मसूद अजहर का मुद्दा आने वाले चुनाव में मुख्य मुद्दा बनकर उभरेगा। समाचारपत्र ने लिखा है कि पुलवामा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जो वातावरण बना रहे थे उसे चीन द्वारा मसूद अजहर को समर्थन दिए जाने से धक्का लगा है। गत दस वर्षों में यह चौथी बार है जब आतंकवादियों को बचाने के लिए चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया हो। समाचारपत्र ने लिखा है कि मोदी द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके हाथ में देश सुरक्षित है जबकि मोदी के शासनकाल में भी कांग्रेस के शासनकाल की तरह कई आतंकी हमले हुए हैं और कश्मीर नीति विफल रही है। पुलवामा और बालाकोट के मुद्दे को भाजपा अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग इसपर प्रतिबंध लगा चुका है।

सियासत (15 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि चीन ने इस आतंकवादी को बचाने का जिस तरह से प्रयास किया है उससे भारतवासियों को झटका लगा है। विश्व के अन्य देशों को चीन के इस रूख की निंदा करनी चाहिए क्योंकि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। जैश-ए-मोहम्मद स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसने भारत में अनेक आतंकवादी हमले किए थे। इसके बावजूद चीन द्वारा उसका समर्थन करना सही कदम नहीं ठहराया जा सकता।

III

पाकिस्तान में पत्रकार निशाने पर

अखबार-ए-मशरिक (23 मार्च) के अनुसार कराची में कुछ पत्रकारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। उनके खिलाफ मस्जिदों में खुत्बा में प्रचार किये जा रहे हैं। इनपर यह आरोप लगाया गया है कि ये पत्रकार विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और लड़कियों तथा महिलाओं को बरगलाकर इस्लाम से दूर कर रहे हैं। एक पत्रकार ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें टेलीफोन द्वारा धमकी के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब महिला दिवस मनाया गया था तब उन्होंने उसकी कवरेज विस्तृत रूप से की थी इसीलिए उनके खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। रैली में शामिल होने वाली महिलाओं को अवारा बताकर उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

IV

काबूल में छह आतंकवादी गिरफ्तार

हमारा समाज (23 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान की सुरक्षा विभाग ने यह दावा किया है कि इस्लामिक स्टेट से संबंधित छह आतंकवादियों को काबूल से गिरफ्तार किया गया है। इस गुट ने जुमा रात को काबूल में हुए हमले की जिम्मेवारी कबूल की है। जुमा रात को जब नव वर्ष का समारोह मनाया जा रहा था तब नगर में कम से कम छह धमाके हुए जिसमें छह लोग मारे गए और 23 घायल हुए। अफगानिस्तान के उपगृहमंत्री नुसरत रहीमी ने दावा किया है कि ये बम पहले से रखे हुए थे जबकि रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि ये धमाके रॉकेटों से हुए हैं।

V

ब्रिटेन में मस्जिदों पर हमले

हमारा समाज (23 मार्च) के अनुसार ब्रिटेन के नगर बर्मिंघम में पांच मस्जिदों पर हमला किया गया और इनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस इन हमलों की जांच कर रही है। मस्जिद फैजल इस्लाम के चेयरमैन युसूफ जमान ने कहा है कि इन हमलों के कारण मुसलमानों में भय फैल गया है और ये समझने लगे हैं कि वे सुरक्षित नहीं हैं मगर हम नमाज पढ़ना बंद नहीं करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। मस्जिदों की सुरक्षा के लिए सभी मस्जिदों के प्रमुखों का एक अधिवेशन बुलाया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि किसी भी हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा।

VI

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज अशरफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (12 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने नंदीपुर पावर परियोजना में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ और पूर्व विधि मंत्री बाबर अवान सहित सात आरोपियों को आरोपित घोषित किया है। अन्य आरोपियों में पूर्व विधि सचिव रियाज कैयानी, मसूद चिश्ती, परामर्शदाता शमिला महमूद, पूर्व सहसचिव रियाज महमूद और पूर्व सचिव शाहिद रफीक शामिल हैं। आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। इन आरोपियों पर यह आरोप है कि इस परियोजना में हुई देरी के कारण पाकिस्तान के खजाने को 27 अरब रुपये का नुकसान पहुंचा है। ज्ञातव्य है कि यह परियोजना पंजाब में पीपुल्स पार्टी के शासनकाल में शुरू की गई थी। जिससे सवा पांच सौ मेगावाट बिजली पैदा होने का दावा किया गया था। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कहा था कि इस भ्रष्टाचार के कारण परियोजना को खटाई में डाला गया जिससे उसका खर्च बढ़कर 22 अरब से 58 अरब तक पहुंच गया।

हमारा समाज (13 मार्च) ने यह आरोप लगाया है कि इस परियोजना में अरबों रुपये की हेराफेरी हुई जिसके कारण पाकिस्तान दो दशक से बिजली की कमी को बूरी तरह से झेल रहा है और अब स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि हर रोज 12 से 18 घंटे तक लोडसेडिंग की जाती है। इसके कारण सारा विकास ठप है। पीपुल्स पार्टी की पंजाब सरकार ने जिला गुजरांवाला के नजदीक नंदीपुर में यह परियोजना लगाने का फैसला किया था और इसका ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया था। मगर यह कंपनी पाकिस्तान सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दी थी इसलिए इस परियोजना के प्रश्न पर जल और विद्युत मंत्रालय और कानून

मंत्रालय में मतभेद उत्पन्न हो गए। विधि मंत्रालय ने इस परियोजना को नियमों के विरूद्ध बताया। सरकारी विभागों के विवाद के कारण इस परियोजना के लिए विदेश से आई 85 मिलियन डॉलर की मशीनें कराची के गोदामों में पड़ी हुई खराब हो गईं। सितम्बर 2012 में चीनी कंपनी ने इस समझौते को रद्द कर दिया और कहा कि इस सौदे में उसे 85 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 2013 में नवाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद पुनः इस परियोजना पर चर्चा शुरू हुई और चीनी कंपनी ने परियोजना शुरू करने का आश्वासन दिया। 2014 में परियोजना शुरू होने की घोषणा की गई और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। मगर इस परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू न हुआ और पांच दिन के बाद इस कारखाने को बंद कर दिया गया। विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि ये मशीनरी फर्निस ऑयल पर चलने के लिए डिजाइन की गई थी मगर बाद में इसे गैस पर चलाया गया। इंजिनयरों ने इस प्लांट को क्रूड ऑयल पर चलाने का प्रयास किया जिससे पांच दिनों में ही मशीनरी ठप हो गईं। चीनी कंपनी ने इस प्लांट की मरम्मत करने की पेशकश की मगर विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली 42 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है जो कि सबसे महंगी है। इसके साथ ही यह परियोजना खटाई में डाल दी गई। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शासनकाल में विशेषज्ञों द्वारा इस पूरी परियोजना की जांच करवाई गई जिसमें कई तरह के घोटाले उजागर हुए। 2016 में प्लांट के रिकॉर्ड में आग लग गई और सारा रिकॉर्ड नष्ट हो गया। रिकॉर्ड नष्ट होने के कारण भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिट गए। बाद में गार्डों ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि यह आग प्लांट के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर लगाई गई थी। 2015 में पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार विभाग ने इसकी जांच शुरू की। मगर इस जांच में अधिकारियों ने कोई सहयोग नहीं दिया और न ही संबंधित रिकॉर्ड ही उपलब्ध कराया। पाकिस्तानी संसद की सार्वजनिक लेखा समिति ने 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। इस जांच के आधार पर अब यह मुकदमा चलाया गया है।

VII

ईसाई महिला को जबरन मुसलमान बनाने के आरोप की जांच

हमारा समाज (18 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान पुलिस ने एक ईसाई महिला को जबरन मुसलमान बनाने और उससे निकाह करने के आरोप की न्यायिक जांच शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में रहनेवाले एक ईसाई व्यक्ति ने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का अपहरण करके उसका जबरन धर्मांतरण करवाया गया और उससे खालिद महमूद नामक व्यक्ति ने निकाह कर लिया। नावेद इकबाल नामक इस ईसाई ने यह भी आरोप लगाया था कि उसने इस अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। नावेद ने यह धमकी दी थी कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह परिवार सहित आत्मदाह कर लेगा। बाद में पुलिस ने उसकी पत्नी को बरामद किया। जबकि दूसरी ओर तीन बच्चों की मां शाइमा इकबाल ने पुलिस में यह बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था और अपनी मर्जी से ही खालिद के साथ निकाह किया था मगर अब मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इस महिला ने अपनी मेडिकल जांच करने से इनकार कर दिया था। इस महिला के पति नवेद इकबाल का दावा है कि जब उसकी पत्नी को बरामद किया गया तो उसके शरीर पर अनेक घाव थे इसलिए उसने बयान भय के कारण दिया था। जब यह मामला समाचारपत्रों में उजागर हुआ तो केन्द्रीय गृह मंत्री शहरयार अफरीदी ने इस मामले की पुनर्जांच करने का आदेश दिया। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं का अपहरण करके उनसे जबरन निकाह करने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। आमतौर पर अभी तक हिन्दू महिलाओं को ही इसका शिकार बनाया जाता रहा है।

पश्चिमी एशिया

I

ईरान और इराक के बीच संबंध सुधारने का प्रयास

सहाफत (12 मार्च) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी इराक के दौरे पर बगदाद पहुंच गए हैं। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी सरकार द्वारा इराक सरकार पर इस बात के लिए निरंतर दबाव डाला जा रहा था कि वह ईरान के साथ अपने संबंधों को न बढ़ाए। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस घटना को ऐतिहासिक बताया है और यह आशा व्यक्त की है कि दोनों देशों के आपसी संबंधों में मजबूती आएगी और व्यापार बढ़ेगा। इस दौरे का विशेष महत्व यह भी है कि अमेरिका द्वारा इस बात का निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि अरब देशों से ईरान को अलग–थलग कर दिया जाए और अमेरिका ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा चुका है। इस समय इराक में जो लोग सत्तारूढ़ हैं वे शिया सम्प्रदाय से संबंधित हैं जबकि ईरान भी शिया देश है। रूहानी ने कहा कि ईरान, इराक को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इराक ईरान से गैस और बिजली खरीदता है और उन दोनों के दौरान इस समय बारह बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है।

इंकलाब (12 मार्च) के अनुसार बगदाद में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में यह दावा किया है कि दोनों देश व्यापार, पर्यटन के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाएंगे। इराक के राष्ट्रपति ने यह स्वीकार किया कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में इराक को ईरान ने बहुत सहयोग दिया है। जहां तक सुरक्षा का संबंध है यह ईरान और इराक का आपसी मामला है। उन्होंने कहा कि हम ईरान और इराक की दोस्ती चाहते हैं मगर यह दोस्ती किसी और देश के खिलाफ नहीं है। हम सभी देशों को आमंत्रण देते हैं कि वे हमारे इस सहयोग में शामिल हों। ईरान के राष्ट्रपति ने इराक सरकार का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उसने लाखों शिया यात्रियों को इराक में शिया धर्मस्थानों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है।

II

यमन में हाउसी विद्रोहियों द्वारा भर्ती

हमारा समाज (23 मार्च) के अनुसार यमन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि हाउसी विद्रोहियों ने ईरान के इशारे पर बच्चों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए चार बड़े गुप्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इनमें ईरानी आतंकवादी इन विद्रोहियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें ईरान द्वारा आधुनिक अस्त्र–शस्त्र और मिसाइल सप्लाई किए गए हैं। सरकारी दावे के अनुसार ईरान ने काफी मात्रा में आधुनिक अस्त्र–शस्त्र तस्करों के माध्यम से यमन के विद्रोहियों को भिजवाए हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार यमनी विद्रोहियों ने अफ्रीकी नागरिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया है और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाउसी विद्रोहियों ने इन अफ्रीकियों को उन क्षेत्रों से भर्ती किया है जिनपर उनका कब्जा है। विद्रोही इन अफ्रीकियों को मोटे वेतन पर भर्ती कर रहे हैं। एक अन्य समाचार में अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि यमन के विद्रोही ईरान के नेताओं के इशारे पर नाच रहे हैं। अल अरेबिया को दिए गए विशेष इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हाउसियों को यह समझ लेना चाहिए कि वे यमन पर कब्जा नहीं कर सकते और न ही वे ईरान के इशारे पर यमनियों को बंधक बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को ईराक, सीरिया और यमन में युद्ध की ज्वाला भड़काने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।

III

सउदी युवराज के विरोधियों के खिलाफ अभियान

इंकलाब (19 मार्च) ने दावा किया है कि सउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विरोधियों का सफाया करने के लिए गुप्त अभियान की मंजूरी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि इस अभियान के तहत सउदी जनता की गतिविधियों की निगरानी की जाती है और विरोधियों को बंधक बनाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में प्रताड़ित भी किया जाता है। यह काम गुप्तचर विभाग के सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। इन्होंने ही पिछले दिनों तुर्की में एक सउदी पत्रकार की हत्या भी की थी। इस हत्या के खिलाफ दुनिया भर में सउदी सरकार को निशाना बनाया गया था। यह भी दावा किया गया है कि इस अभियान के तहत कई महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। सउदी सरकार ने इस तरह के किसी भी अभियान का खंडन किया है।

IV

कतर द्वारा तुर्की से टैंकों की खरीद

हमारा समाज (19 मार्च) के अनुसार कतर ने तुर्की से एक सौ टैंक खरीदने का समझौता किया है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने बताया कि कतर तुर्की से बीएमसी बख्तरबंद गाड़ियां और अलतिया 40 मॉडल के टैंक दो वर्ष के अंदर खरीदेगा। इसके अतिरिक्त अन्य जंगी सामान भी तुर्की से खरीदा जाएगा। जो टैंक खरीदे जा रहे हैं वह इलेक्ट्रॉनिक कमांड और कंट्रोल व्यवस्था से संचालित हैं। इनपर 120 मिलीमीटर की बंदूकें लगी हुई हैं। तुर्की ने इन टैंकों को 2011 में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। यह भी पता चला है कि तुर्की और कतर के बीच सुरक्षा का एक समझौता हुआ है जिसके तहत कतर ने तुर्की को अपनी भूमि पर एक बड़ा सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये टैंक हालांकि तुर्की में बनाए गए हैं परन्तु इनमें विदेशी पूर्जे भी लगाए गए हैं। इसका इंजन जर्मनी का बनाया हुआ है। जानकार सूत्रों का कहना है कि जर्मनी इन टैंकों को सीरिया और इराक में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए संभव है कि तुर्की को यह इंजन यूक्रेन से खरीदना पड़े।

V

ईरानी आतंकवादियों को सजा

अखबार-ए-मशरिक (18 मार्च) के अनुसार केन्या की सरकार ने दो इस्लामी आतंकवादियों को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है। इनका संबंध ईरान की विदेशी गुप्तचर एजेंसी से बताया जाता है। न्यायालय ने यह फैसला किया है कि उनकी सजा खत्म होने के बाद उन्हें ईरान भेज दिया जाएगा। केन्या सरकार ने आरोप लगाया है कि ईरानी दूतावास केन्या में इस्लामी उग्रवादियों की घुसपैठ करवा रहा है। केन्या के सरकारी वकील जनरल नुरूद्दीन हाजी ने आरोप लगाया है कि ईरानी राजदूत कुछ आतंकवादियों को गुप्त रूप से वापस ईरान भेजने का प्रयास कर रहा था मगर केन्या की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इन सारे घोटाले का पर्दाफाश हो गया।

VI

ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी

अखबार-ए-मशरिक (24 मार्च) के अनुसार अमेरिका ने ईरान पर अनेक कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं ताकि ईरान परेशान होकर अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेबनान में अपने दौरे के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि अरब देशों में ईरान का जो प्रभाव बढ़ रहा है वह अमेरिका के लिए खतरनाक है इसलिए सरकार ने ईरान के 31 वैज्ञानिकों और रक्षा अनुसंधान कार्यालय से संबंधित लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिनलोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए 18 प्रमुख सैनिक भी शामिल हैं। इन प्रतिबंधों के कारण इन व्यक्तियों और कंपनियों से संबंधित सभी खाते अमेरिकी बैंकों में सीज कर लिए गए हैं और उनसे जो कोई लेनदेन करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके अमेरिका में प्रवेश और यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता किया था मगर बाद में अमेरिका ने इस समझौते को भंग कर दिया। अमेरिका का कहना था कि यह समझौता उसके हित में नहीं है और इसके द्वारा ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और भी सशक्त बना सकता है। अमेरिकी शासकों का कहना है कि यह फैसला इजरायल से मिली सूचना के आधार पर किया गया है। इन सूचनाओं के अनुसार ईरान ने अमाद योजना बनाई है जिसके तहत वह कभी भी परमाणु उत्पादन कार्यक्रम को पुन: शुरू कर सकता है।

VII

इस्लामिक स्टेट का खात्मा?

इंकलाब (24 मार्च) के अनुसार अमेरिका समर्थक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) का कहना है कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की हार के बाद पांच वर्ष पूरानी खिलाफत का खात्मा हो गया है और अब उसका नामोंनिशान मिट गया है। मगर समाचारपत्र ने चेतावनी दी है कि नाईजीरिया, यमन, अफगानिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों में उस जैसे संगठन मौजूद हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि कुर्दों के संगठन एसडीएफ ने इस्लामिक स्टेट से पीड़ितों लोगों की शरण के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं और इस संगठन का पूर्णत: सफाया हो गया है। ज्ञातव्य है कि यह संगठन 2013 में इराक पर हुए अमेरिकी हमले के बाद अलकायदा के इशारे पर बनाया गया था और इसने 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति का तख्ता पलटने का प्रयास किया था। 2014 में इसने इराक और सीरिया के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया और नई खिलाफत की घोषणा की। इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में 80 लाख लोग थे और इसने तेल, डाकें और अपहरण के द्वारा लोगों से करोड़ों डॉलर बटोरकर उससे हिंसा की ज्वाला को भड़काया।

अन्य

I

इलाहाबाद का नाम बदलने पर खटखटाया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी के नेता जगत पांडेय, जावेद अहमद और वकील फरमान अली नकवी ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय किया है। विख्यात वकील राजीव धवन ने यह घोषणा की है कि वे यह मुकदमा बिना कोई फीस लिए लड़ेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया है जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। वकील फरमान अली ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के वकीलों का एक पैनल बनाया गया है जो इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

II

जम्मू-कश्मीर में नए राजनीतिक दल की घोषणा

अखबार-ए-मशरिक (18 मार्च) के अनुसार पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मुवमेंट की घोषणा कर दी है। इस समारोह में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष शहला रशीद और बांदीपोरा के हाफिज कुरान और डॉ. गुलाम मुस्तफा खान ने भी इस नई पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। फैजल ने यह घोषणा की कि पिछले सत्तर वर्ष में हमें सिर्फ धोखा मिला है। यह नई पार्टी किसी विशेष क्षेत्र या धर्म तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि इसके दरवाजे रियासत के सभी क्षेत्रों के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने में हम विश्वास करते हैं क्योंकि वे हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जनता के लिए आईएएस को ठोकर मारी है। इस अवसर पर फिरोज पीरजादा और बल्देव सिंह ने भी इस नई पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर कई अन्य प्रमुख लोग भी इस पार्टी में शामिल हुए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील इकबाल ताहिर, राजा महमूद, बशीर अहमद आदि शामिल हैं।

III

पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो अल्पव्यस्क हिन्दू लड़कियों का अपहरण करके उनका जबरन धर्मांतरण किया गया। इसके बाद जबर्दस्ती उनका निकाह भी करा दिया गया। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान स्थित भारतीय राजदूत से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि यह हमारा अपना मामला है। उन्होंने कहा है कि आप पहले भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रयास करें। फवाद चौधरी ने कहा है कि जहां तक इस घटना का संबंध है हम इसकी जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अनुसार दो बहनों का अपहरण करके उन्हें जबरन

मुसलमान बनाया गया और इसके बाद मुसलमानों से उनका निकाह कर दिया गया। मीडिया में हंगामा मचने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह निर्देश दिया है कि इन दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद किया जाए और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाए।

IV

वक्फ संपत्ति के अवैध कब्जे को मुक्त करवाने के लिए अभियान

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया तहफ्फुज-ए-ओकाफ कांफ्रेंस ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जे को मुक्त करने का अभियान चलाया है। इस संगठन के अनुसार देश में 50 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिनपर सरकारी और प्राइवेट लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हाल में ही नई दिल्ली में कर्बला जोरबाग में अवैध कब्जे से कानूनी लड़ाई लड़कर सैंकड़ों करोड़ की भूमि वापस ली गई है। इसके बाद शिया और सुन्नी विद्वानों ने देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय किया है। कर्बला शाह मर्दान में आयोजित एक समारोह में विख्यात शिया नेता मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने हजरत अली की तलवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के हवाले की और उनसे देश भर में यह अभियान शुरू करने का आग्रह किया। महमूद प्राचा ने यह घोषणा की कि जो लोग वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं वे स्वयं ही वक्फ संपत्ति को छोड़ दें या उसको लीज पर लेकर उसका किराया अदा करें। उन्होंने कहा कि देश भर में 50 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। अगर हम इनमें से दस प्रतिशत भी मुक्त करवा लेते हैं तो फिर कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। हमें फिरकों से उपर उठकर इस अभियान को चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मस्जिदें भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने नियंत्रण में ले रखी हैं उनमें हमें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अभी तक यह अभियान केवल दिल्ली और लखनऊ तक ही सीमित था मगर अब देश भर में इसका विस्तार किया जा रहा है।

V

कराची में इस्लामी नेता पर हमला

हमारा समाज (23 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के नगर कोरंगी में एक इस्लामी मदरसे के प्रमुख पर हमला किया गया। इस हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी बाल-बाल बच गए परंतु उनके दो अंगरक्षक मारे गए। पुलिस के अनुसार दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार सशस्त्र लोगों ने एक कार पर गोली चलाई जिसमें ये दोनों लोग मारे गए। जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस कप्तान गुलशन ताहिर नुरानी ने कहा है कि मुफ्ती तकी मदरसा से गुलशन इकबाल जा रहे थे तभी उन पर हमला किया गया। वे वहां की मस्जिद में कई साल से जुमा का खुत्बा देते थे। मुफ्ती तकी की गिनती देवबंदी विचारधारा के प्रमुख चिंतक में की जाती है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने पुलिस से इस घटना का विवरण मांगा है। मुफ्ती के भतीजे सरवर उस्मानी ने दावा किया है कि जब यह हमला हुआ तो मुफ्ती के साथ उनके अन्य परिवारजन कार में थे मगर वे बच गए हैं। मजलिस वजाहत अल मुस्लिमीन के अध्यक्ष अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी ने उलेमा पर हमले की निंदा की है और कहा है कि आतंकवादी देश का अमन तबाह करने पर तुले हुए हैं।

VI

चीन में 13 हजार जिहादी गिरफ्तार

इंकलाब (19 मार्च) के अनुसार चीन सरकार ने सिक्यांग में अल्गोहर मुसलमानों के खिलाफ चलाए गए अभियान का उल्लेख करते हुए कहा है कि 2014 के बाद 13 हजार इस्लामी आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन ने दस लाख से अधिक मुसलमानों को अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है। चीन सरकार ने दावा किया है कि आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी रहेगा। सरकारी बयान में कहा गया है कि सिक्यांग चीन का भाग है मगर वहां पर काफी देर से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। एक व्हाइट पेपर के अनुसार अब तक इस क्षेत्र में डेढ़ हजार से अधिक आतंकवादियों को मारा जा चुका है। तेरह हजार आतंकवादी पकड़े गए और दो हजार से अधिक बम बरामद किए गए। तीस हजार से अधिक लोगों को अवैध धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में सजाएं सुनाई गईं। आतंकवाद के प्रचार से संबंधित साढ़े तीन हजार दस्तावेजें बरामद की गईं। अल्गोहर काउंसिल ने दावा किया है कि चीन सरकार मुस्लिम विरोधी गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए झूठे दावे कर रही है। समाचार एजेंसी एएफपी ने यह दावा किया है कि चीन में जगह–जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि सिक्यांग में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध है। कोई भी नागरिक 50 वर्ष की आयु से पहले दाढ़ी नहीं रख सकता और न ही मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमजान में रोजा रखने की ही अनुमति है।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

Latest Publications

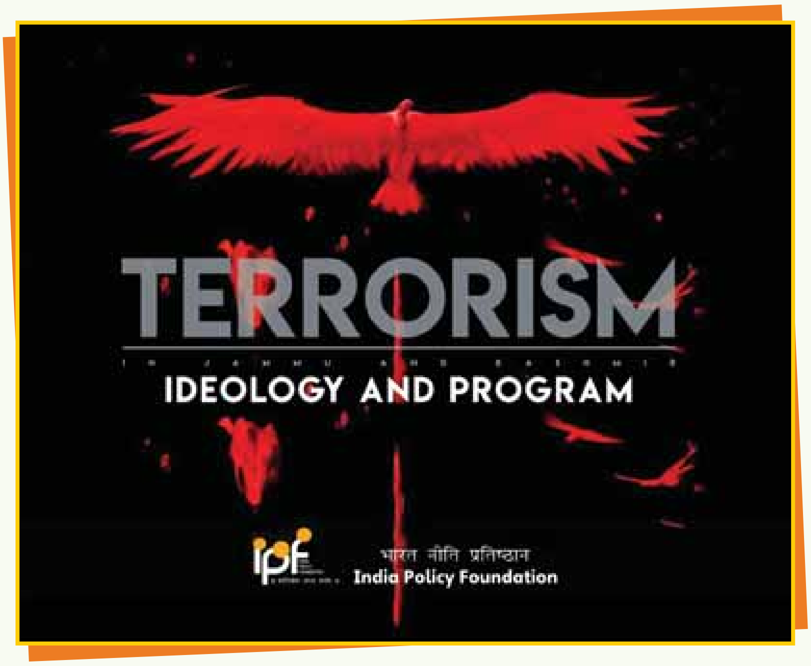

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org